प्रकाशनार्थ

पटना, **2** मई। “एविडेंस से एक्शन तक: पटना में पर्यावरणीय संरक्षण और शहरी भविष्य” शीर्षक का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी तथा एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

इस अवसर पर बोलते हुए बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के महानिदेशक एवं मुख्य जांच आयुक्त श्री दीपक कुमार सिंह (एसीएस) ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले विचारों को लागू करना होगा। उदाहरण के लिए, कचरा प्रबंधन तभी सुधरेगा जब लोग कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग-अलग करना शुरू करेंगे।

लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर स्वाति ढिंगरा ने पटना में कचरा पृथक्करण पर किए गए अपने शोध के निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जो उन्होंने प्रोफेसर स्टीफन मशीन के साथ मिलकर किया था। घरों को कचरा अलग करने का प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रशिक्षण से पहले और बाद में इसके परिणामों को मापा गया। पाया गया कि पृथक्करण के लाभ प्रशिक्षण पर हुए खर्च से पाँच गुना अधिक था। अध्ययन समाप्त होने के बाद भी लोगों ने कचरा अलग करना जारी रखा। उन्होंने यह भी बताया कि पटना नगर निगम के राजस्व व्यय का 40 प्रतिशत हिस्सा कचरा प्रबंधन पर खर्च होता है।

नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निशीथ प्रकाश ने “पर्यावरणीय दृष्टिकोण और व्यवहार के अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव” विषय पर अपने शोध के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। उनके अध्ययन में पटना के स्कूली बच्चे शामिल थे। उन्होंने पाया कि बच्चे अपने माता-पिता की तुलना में विद्यालय के पर्यावरणीय पाठ्यक्रम पर अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं।

बिहार सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त श्री त्रिपुरारी शरण ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई तभी सफल होगी जब इसे सभी नागरिकों की सहभागिता से जोड़ा जाए। लोगों को इसके गंभीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री आमिर सुबहानी ने कहा कि सरकार जनता को केंद्र में रखकर सतत और न्यायसंगत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। राजस्व परिषद, बिहार सरकार की अध्यक्ष-सह-सदस्य श्रीमती हरजोत कौर बुमराह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जन-शिक्षा और सुधार साथ-साथ चलने चाहिए।

आईआईटी पटना के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. नलिन भारती ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन का वादा जमीन पर पूरी तरह से लागू होता नहीं दिख रहा है। उदाहरण के लिए, आज भी पटना की कुछ सड़कों पर कचरा फैला हुआ देखा जा सकता है। विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, बिहार सरकार के निदेशक (संचालन) डॉ. आलोक रंजन ने कचरा प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं से निपटने वाले सरकारी विभाग मिलकर कार्य करें।

कार्यक्रम की शुरुआत में आद्री की एसोसिएट प्रोफेसर एवं सदस्य-सचिव डॉ. अश्मिता गुप्ता ने सभी विशिष्ट वक्ताओं का परिचय कराया।

सम्मेलन में भारतीय मौसम विभाग के डॉ. आशीष कुमार, सीएसईपी नई दिल्ली के श्री उत्कर्ष पटेल, एलएसई के वरिष्ठ नीति फेलो जोसेफ फेयरटॉग, डॉन बॉस्को अकादमी के श्री एलन कॉवेल, आईआईटी धनबाद के प्रोफेसर सुरेश पांडियन एलुमाला तथा आईएसआई दिल्ली की डॉ. रश्मि बरुआ सहित कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे।

पटना के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के अनेक छात्र-छात्राओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

(अभिषेक प्रसाद)